Title: Need to make Ganesh Sugar mills, under N.T.C. in Maharajganj district, Uttar Pradesh viable- Laid.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज) : महोदय, जनपद महराजगंज पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा एवं गरीब जिला है । स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कं. लि. की ईकाई गणेश सुगर मिल्स की स्थापना जैपुरिया बंधुओं द्वारा सन् १९३२ में की गयी थी । यह चीनी मिल्स आनंद नगर कस्बे के मध्य लगभग ३३.४७ एकड़ भूमि में स्थित है और इसके पास ७३० एकड़ के दो कृषि फार्म भी हैं । इस मिल को बाद में भारत सरकार के राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया । अधिगृहण के पश्चात यह सुगर मिल सुचारू रूप से चली ही नहीं वरन मुनाफा भी देती रही,परंतु शुरू से ही राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा न तो इसका विस्तारीकरण किया गया और न ही इसकी पेराई क्षमता बढ़ाने की ही कोशिश की गयी । कुप्रबंध एवं वित्तीय अभाव के कारण यह मिल सन् १९९०-९१ से लाभ के बजाय घाटा उठा रही है । इतना ही नहीं भारत सरकार द्वारा गारंटी न प्रस्तुत करने के कारण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट की सुविधा भी निरस्त कर दी गयी । जिस कारण गन्ना किसानों को न तो मूल्य का भुगतान हो पाया और न ही पर्याप्त गन्ने की खरीद ही की जा सकी जिसके कारण मिल केवल ६२ दिन चलने के बाद ३ फरवरी, १९९४ को बंद हो गयी । लगातार घाटे के कारण इस मिल को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्वास संस्थान (बीएफआईआर) को संदर्भित किया गया था जिसने इसे बीमार ईकाई घोषित कर इसके पुनर्वास की योजना भेजने की संस्तुति की परंतु इस संबंध में भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी । राष्ट्रीय वस्त्र निगम, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा बराबर इस मिल को चलाने की अनिच्छा व्यक्त की गयी और मिल को चलाने के लिए सरकार द्वारा अनावश्यक धन भी उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण इस मिल के परिसमापन के आदेश दिये गये । इस आदेश के विरूद्ध कर्मचारियों ने अपील दायर की जो खारिज कर दी गयी और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उनकी याचिका भी खारिज कर दी ।

अब इस समय कम्पनी रजिस्ट्रार कानपुर द्वारा इस औद्योगिक ईकाई के परिसमापन का कार्य शुरू किया जाना है जिसके परिणामस्वरूप इसके ७०० कर्मचारी वेतन से वंचित हो जायेंगे उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेगा, इस पिछड़े क्षेत्र का गन्ना किसान बर्बाद हो जायेगा । गन्ना किसानों को बकाया राशि २३४ लाख रूपया डूब जायेगा ।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बीमार औद्योगिक ईकाई के पुनर्वास की कार्यवाही शुरू की जाये, वहां सरकार द्वारा आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाये, कर्मचारियों के वेतन और गन्ने के बकाये मूल्य का भुगतान कराकर क्षेत्र को बर्बाद होने से बचाया जाए ।